Title: Regarding development works under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

श्री प्रेमदास (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आठ-दस साल पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना की एक स्कीम चली। मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन था, उसमें प्रस्ताव पास करने का मौका मिला था। उसमें यह था कि दो हजार वाली आबादी के गांव पहले जोड़े जाएंगे, उसके बाद एक हजार आबादी वाले गांव जोड़े जाएंगे और फिर पांच सौ आबादी के गांव जोड़े जाएंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी एक हजार, दो हजार आबादी के तमाम ऐसे गांव पड़े हुए हैं, जो सड़क से नहीं जुड़े। प्रधानमंत्री सड़क योजना में पांच साल का मेंटीनेंस था, आज दो-तीन साल बाद सड़क टूट जाती है और कोई मेंटीनेंस नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजती हैं, लेकिन जो हम लोग मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता है।

13.00 hrs.

हम लोग गांवों में जाते हैं, तो देखते हैं कि तमाम गांव बगैर सड़कों के हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर बनने वाली सड़कों के प्रस्ताव सांसद से लिए जाएं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र औरैया में ऐसे तमाम गांव हैं जो चार-चार और दस-दस किलोमीटर दूर हैं, जिनमें आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उनमें सड़कें बनाई जाएं। जैसे ऐली गांव है, जमालपुर गांव है और छोकर की मडैया पुरवा है। इन्हें सड़कों से जोड़ा जाए।

महोदया, 18 और 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से सड़कें बनती हैं, लेकिन राज्य सरकारों के अधिकारी और कर्मचारी उनमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं, जिसके कारण बहुत घटिया किस्म का काम हो रहा है। इसकी जांच कर के हमें अवगत कराया जाए, क्योंकि इसमें केन्द्र सरकार का पैसा लग रहा है, इसलिए केन्द्र सरकार इस बारे में एक समिति बनाए, ताकि इस योजना में जो अरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा सके।